

THE PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE HUNDRED AND SEVENTY-SIXTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 26th February, 1996/7th Phalguna, 1917 (Saka)

RAJYA SABHA

*Monday, the 26th February, 1996/
7th Phalguna, 1917 (Saka)**(The House met at twenty minutes past twelve
of the clock)**[Mr. Chairman in the Chair.]**(The National Anthem was played)*

MEMBER SWORN

Shri K.L. Poswal (Haryana)

PRESIDENT'S ADDRESS LAID ON
THE TABLE

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 26th February, 1996.

[Placed in Library, See No. LT-8989/96] *(Text of the Address delivered by the President (Dr. Shanker Dayal Sharma) In Hindi)*

माननीय सदस्यगण,

मैं संसद के इस पत्र में आपका स्वागत करता हूँ। 10वीं लोक सभा ने अपने कार्यों को काफी हर तक पुरा कर लिया है तथा आपके कुशल नेतृत्व में देश के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस अवसर पर मैं, आप सभी को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से की गई सेवाओं के लिए बधाई देता हूँ।

राष्ट्र ने महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनायी। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहिंसा

एवं अन्य गांधीवादी सिद्धान्तों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए गांधी शान्ति पुरस्कार की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। प्रथम गांधी शान्ति पुरस्कार डॉ. जुलियस के. न्यरेरे को प्रदान किया गया। गांधी जयंती समारोह 31 जनवरी, 1996 को नई दिल्ली के बाल्मिक मंदिर परिसर में स्थित "बापू कुटीर" में गारिमामय समारोह के साथ संपन्न हुआ। गांधी जी प्रायः वहां ठहरा करते थे।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। विभिन्न समुदायों तथा वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए सरकार आगामी महीनों में और अधिक सतर्कता बरतेगी।

आंतकवाद तथा विद्रोही ताकतों पर काबू पा लिया गया है। अलगावादी प्रवृत्तियों को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में सुरक्षा बलों का कार्य काफी सरहानीय रहा है। परन्तु पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में हथियार गिराए जाने की घटना से यह आवश्यक हो गया है कि सतर्कता निरंतर बरती जाए। इस घटना की छानबीन काफी तेजी से की जा रही है, और देश में एंव देश के बाहर इससे जुड़े तत्वों का पता लगाया जा रहा है। देश के हवाई मार्गों की प्रभावी चौकसी सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

जम्मू व कश्मीर में उग्रवादियों तथा भाड़े के विदेशी सैनिकों के विरुद्ध सुरक्षा-बलों की संयुक्त कार्रवाई तथा वहां विकास संबंधी काग्रकलापों में तेजी लाने के फलस्वरूप स्थिति सुधार आया है। इससे राजनीतिक गतिविधियों को बहाल करन संभव हो पाया है। संसद ने 1995-96 में संतुलित बजट सहित पारित किया, और पिछले कई वर्षों के बाद पहली बार यह आशा की जा रही है कि योजनागत परिव्यय को पूरी तरह से विकास योजनाओं पर ही व्यय किया जा सकेगा, और गैर-योजना संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए

इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यद्यपि सरकार को इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर 17 जुलाई, 1996 तक करनी पड़ी, फिर भी सरकार राज्य में शीघ्रताशीघ्र चुनी हुई सरकार की वहाली के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं। पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक कारगर संस्था के रूप में उभरकर सामने आई हैं। असम में कारबी अंगलांग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के स्वायत्त जिला परिषदों को और अधिक शक्तियाँ देने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया गया है।

आर्थिक परिदृश्य में लगातार सुधार हो रहा है। 1991-92 के बाद के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में अपेक्षाकृत काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 में यह बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1994-95 में वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू में सुधार हुआ, और यह सकल घरेलू उत्पाद की 24.4 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में औद्योगिक उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उल्लेखनीय सुधार है।

इसके साथ-साथ, चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में निर्यात में 24.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के कारण और अधिक आयात भी करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति काफी अच्छी है, और अब यह लगभग 16 विलियन डालर है।

मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर अगस्त, 1991 में लगभग 17 प्रतिशत तक पहुँच गयी थी। परन्तु अब इसे नियंत्रित कर लिया गया है, और यह चालू वर्ष में घटकर 5 प्रतिशत के आसपास आ गई है, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम है। कृषि क्षेत्र को मिले व्यापक प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और उसका पर्याप्त भंडार है। आम उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखी गयी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है, और पुनर्व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करके देश के सबसे निर्धन इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त रियायतें दी गयी है।

लघु उद्योग क्षेत्र का योगदान विनिर्माण के क्षेत्र में हुए उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है, और यह देश के कुल निर्यात का 37 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, और

वर्ष 1994-95 के अंत तक 146 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस क्षेत्र से वर्ष 1991-92 में 13,883 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया था। अनुमान है कि यह वर्ष 1994-95 में बढ़कर 26,400 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 1994-95 में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में 4059 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई। इसी वर्ष इस क्षेत्र में 53.46 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। खादी रामोद्योग निगम को इस वर्ष पहली बार एक हजार करोड़ रुपये का सहायता संघ ऋण दिया गया है। इसमें से खादी ग्रामोद्योग निगम ने लगभग अवसर पैदा करने के लिए जनवरी, 1996 के अंत तक कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनकी लागत लगभग 235 करोड़ रुपये है।

हमारी कृषि नीति मृदा एवं जल की एकीकृत रूप में सर्वोत्तम उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करने की रही है। आठवीं योजना के दौरान वर्षार-प्रधान क्षेत्रों के लिए पुनर्संगठित राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम का विस्तार 13 राज्यों के 149 जिलों के 946 प्रखंडों तक किया गया है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम का विस्तार 7 राज्यों के 36 जिलों के 227 प्रखंडों तक कर दिया गया है। इन कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से लागू किया जा रहा है।

वर्ष 1994-95 में 19 करोड़ 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का उत्पादन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। चीनी का उत्पादन भी 1994-95 में लगभग 148.85 लाख मीटरी टन में रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया। सरकार ने चीनी की उपलब्धता और कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव के संबंध में एहतियात के तौर पर इस वर्ष चीनी का बफर स्टॉक पांच लाख मीटरी टन बनाया है।

वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थागत एजेन्सियों के माध्यम से 21,113 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरित किए गए, जबकि वर्ष 1995-96 में इनका वितरण 26,450 करोड़ रुपये तक हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1994-95 के दौरान 135.64 लाख मीटरी टन रसायनिक उर्वरकों की खपत हुई थी, तथा वर्ष 1995-96 में इनकी खपत बढ़कर 156.64 लाख मीटरी टन होने की आशा है।

सरकार गरीबों की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग है। गरीबी का उन्मूलन करने के कारगर कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है, यह ग्रामीण विकास, रोजगार

सृजन, आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि मदों के लिए आंबटनों में हुई पर्याप्त वृद्धि से परिलक्षित होता है ।

वर्ष 1985-86 और 1994-95 के बीच इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख मकानों का निर्माण किया गया । इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1995-96 में एक हजार करोड़ रूपए के बजट प्रावधान से 10 लाख मकानों के निर्माण का वृहत कार्यक्रम शुरु किया गया है, और निर्माण कार्य जोरों पर है । इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए और अधिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपाय किए जा रहे हैं ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान 1,9,154 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा । इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर मुहैया कराना है । वर्ष 1995-96 के लिए इस योजना के तहत 2.6 लाख व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है ।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरु किया है, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, प्रसुति-सुविधा और गरीब परिवारों में अकेले कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर एकमुश्त राशि प्रदान करने की व्यवस्था है । इस पैकेज के साथ-साथ समूह बीमा जीवन बीमा की एक अग्रणी योजना शुरु की गई है, जिसमें गरीबों के लिए घटी दर पर प्रीमियम की व्यवस्था है ।

शहरी गरीबों की समस्याओं से एकीकृत रूप से निपटने के लिए 50 हजार से एक लाख की आबादी वाले श्रेणी-2 के सभी 345 शहरों में नवम्बर, 1995 में एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन योजना शुरु की गई । इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

सरकार ने जिला स्तर एवं उससे निचले स्तरों पर संचालित केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में पंचायतों और नगरपालिकाओं की भूमिका एवं शक्तियों का दायरा बढ़ा दिया है । इस पहल के कारण सबसे निचले स्तरों पर दस लाख से अधिक महिलायें नेतृत्व करने और निर्णय लेने की स्थिति में होंगी । इन निकायों को समुचित वित्तीय एवं प्रशासनिक दायित्व सौंपे जाने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है ।

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत विशेष घटक योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के

लिए आंबटनों, तथा स्वैच्छिक संगठनों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की गई है । सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निर्वाह एवं अन्य भर्ती की दरों में भी संशोधन किया है ।

मल-सफाई के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई है । इस योजना के प्रारम्भ होने से अब तक लगभग ऐसे 94 हजार व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया गया है तथा 2.5 लाख व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है ।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने स्व-रोजगार संबंधी कार्यों के लिए अब तक 131.64 करोड़ रूपए वितरित किए हैं । सरकार ने अब तक 122 कोचिंग केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में समान रूप से भाग ले सकें ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने राज्य स्तरीय एजेन्सियों के साथ संपर्क स्थापित किया है । निगम स्व-रोजगार के लिए उनके माध्यम से ऋण वितरित कर रहा है । वक्फ बोर्डों के प्रभावी और लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए पहली जनवरी, 1996 से वक्फ अधिनियम, 1995 लागू किया गया है । निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी से राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है । मंदबुद्धि व्यक्तियों और दिमागी पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों की पूर्ण देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने के बारे में विधेयक लोक सभा में पेश किया गया है ।

वैक्सिन से रोकी जा सकने वाली छः बीमारियों से बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए चलाए जा रहें टीकाकरण कार्यक्रम के अभी से उतसाहवर्द्धक नतीजे मिलने शुरु हो गए हैं । सन् 2000 तक पोलियो उन्मूलन के विश्व लक्ष्य को देखते हुए 9 दिसम्बर, 1995 को पूरे देश में 3 वर्ष तक के आयु वर्ग के साढ़े सात करोड़ से भी अधिक शिशुओं को पोलियो टीके की पूरक खुराक दी गई । इस कार्यक्रम का दूसरा दौर 20 जनवरी, 1996 को चलाया गया । आने वाले वर्षों में भी पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा ।

सन् 2000 तक शिक्षा के लिए सकल घरेलु उत्पाद के 6 प्रतिशत आबंटन का लक्ष्य प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए शिक्षा क्षेत्र के लिए आबंटन राशि में निरन्तर वृद्धि की जा रही है। सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के अंत तक 110 जिलों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा। इस शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षा मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियानों का विस्तार 368 जिलों में, और साक्षरता उपरान्त अभियानों का विस्तार 159 जिलों में किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को पोषण-आहार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से तीन वर्ष में लगभग 11 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।

पिछले पांच वर्षों से देश में औद्योगिक संबंध परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हड़तालें एवं तालाबंदियों की संख्या तथा बेकार श्रम दिवसों की संख्या में बहुत कमी आई है। सरकार नवम्बर, 1995 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत एक करोड़ 90 लाख औद्योगिक कामगारों और उनके परिवारों को पहली बार आजीवन सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

हमने अपने माध्यस्थम कानून को अंतरराष्ट्रीय सोच के अनुरूप बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह अध्यादेश, 1996 प्रख्यापित किया है। इस अध्यादेश से तथा विवादों के समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के लिए किए गए अन्य उपायों से यह आशा की जाती है कि भारत इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शीघ्र ही दक्षिण एशिया क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरेगी।

पिछले वर्ष हमारे वैज्ञानिकों की उलब्धियां उल्लेखनीय रही, जो भविष्य के लिए हमारे मन में विश्वास पैदा करती हैं।

इनसैट-2सी और आई.आर.एस.- 1सी उपग्रहों को पिछले दिसम्बर में सफलतापूर्वक छोड़े जाने से अति आधुनिक अंतरिक्ष प्रणालियों के अभिकल्प, निर्माण और संचालन की हमारी क्षमताओं का एक बार फिर प्रदर्शन हुआ है। ये आग्रह हमारे दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम एवं

संसाधन कार्यक्रमों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वर्ष 1996-97 में इनसैट-2डी और 1997-98 में इनसैट-2ई एवं आई.आर.एस. - 1डी छोड़ने की हमारी योजना है। हमने अपने इनसैट वर्ग के उपग्रह को छोड़ने के लिए जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में भी अच्छी प्रगति की है।

इस वर्ष का ककरापार स्थित दसवां परमाणु शक्ति रिएक्टर संतोषजनक ढंग से स्थापित हो गया है, और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। ट्राम्बे में स्थित रिसर्च रिएक्टर पूरे देश में 300 से अधिक चिकित्सा संस्थानों में निदान एवं उपचार के लिए 60,000 से अधिक कित उपलब्ध करा चुका है।

भारत के पड़ोसी कुछ भागों में वर्ष 1995-96 में सुरक्षा की दृष्टि से अनिश्चिता रही है। पाकिस्तान का अत्याधुनिक हथियार और यूरेनियम संवर्धन संबंधी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का लगातार प्रयास करना हमारे लिए गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के इन प्रयासों से हमारे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, और इससे हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र की सुरक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है। फिर भी इस संबंध में सरकार इनकी क्षमता बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण भी हमारी सशस्त्र सेनाओं की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की भावना के लिए उनकी सराहना करेंगे।

रक्षा अनुसंधान में कार्यरत हमारे वैज्ञानिकों के एकीकृत प्रयासों से ही हल्का लडाकू विमान नवम्बर, 1995 में राष्ट्र को सौंपा गया। इस वर्ष के अंत तक इसकी परीक्षण उड़ानें शुरू हो जाएंगे। मुख्य लडाकू टैंक अर्जुन को सेना में शामिल करने की दृष्टि से पूर्णतः विकसित कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बहु-आयामी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्चकोटि के सुपर कम्प्यूटर का विकास किया है, जिससे बहुत लम्बे समय से महसूस की जा रही है आवश्यकता की पूर्ति हुई है, तथा इस क्षेत्र में हम और अधिक आतिर्भर हैं।

विदेश नीति के मामले में पड़ोसी राष्ट्रों से हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए। भूटान के साथ हमारे पारम्परिक निकट संबंध इस वर्ष और अधिक घनिष्ठ हुए हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन अधिकारी की अप्रैल, 1995 में की गई भारत की यात्रा और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देऊचा की इस माह के शुरू में की गई यात्रा

से आपसी समझ और अधिक बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 1995 में मालदीव में इंदिरा गांधी स्मृति अस्पताल का उद्घाटन किया। यह उस देश के साथ मैत्री और सहयोग की हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध में सौहार्द और विश्वास पर आधारित है। बंगलादेश के साथ हमारे व्यापार संबंधों में सुधार हुआ है। साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ा है। चीन के साथ लगातार उच्च स्तर पर बातचीत से हमारे संबंधों में गतिशीलता बनी हुई है। हमारे प्रयासों से दक्षिण एशिया में, केवल पाकिस्तान को छोड़कर, अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अधिक अच्छे हुए हैं। हम पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हैं कि वह भारत के साथ टकराव का रास्ता छोड़कर सभी अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय वार्ता की हमारी पेशकश पर रचनात्मक रवैया अपनाए।

पिछले वर्ष 7 दिसम्बर 1995 से दक्षिण एशिया अधिमन्त्र्य व्यापार करार के लागू हो जाने से "सार्क" की प्रगति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गयी। भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा पारगम के बारे में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर होना मध्य एशिया के साथ हमारे संपर्कों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे वाणिज्यिक एवं अन्य सम्पर्कों के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच सुगम जल-भूतल मार्ग स्थापित हो सकेगा। "आसिमान" भारत को संवाद साझेदारी का पूर्ण दर्जा देने पर सहमत हो गया है। इससे भारत और "आसिमान" के बीच बढ़ते हुए आपसी हितकारी संपर्कों का पता चलता है।

रूसी संघ के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ बना रहा। इस देश के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग की और संभावनाओं का भी पता लगाया है। भारत-संयुक्त राज्य अमरीका संबंध, विशेषकर आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में और प्रगाढ़ हुए। माले, मारीशस, नामीबिया जिम्बावे, मिस्त्र, बुरकानी फासो और घाना की उच्चस्तरीय यात्राओं से अफ्रीकी महाद्वीप के इन देशों के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला।

भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मार्च, 1995 में डैनमार्क में आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, अक्तूबर, 19695 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 50वीं वर्षगांठ की विशेष बैठक और उसी माह कोलम्बिया में आयोजित किए गए 11वें गुटनिरपेक्ष शिखर-सम्मेलन में विकासशील देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य मामलों को उठाने में मुखर रहा है। निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में की जा रही वार्ताओं में भारत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। परन्तु हम परमाणु अग्रसर संधि का अनिश्चित समय के लिए प्रभावी होना सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के मार्ग में बाधक मानते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य परमाणु हथियार वाले राज्यों के परमाणु शस्त्रगारों को उचित ठहराना है।

चूंकि यह सत्र संक्षिप्त अवधि का होगा, अतः इस सत्र के दौरान केवल आवश्यक विधायी कार्यों पर ही विचार हो जाएगा। पिछले सत्र के बाद से प्रख्यापित कुछ अध्यादेश संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 1996-97 के अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपके समक्ष इस उद्देश्य से रखा जाएगा कि उस वर्ष की अवधि विशेष के लिए व्यय प्राधिकृत करते हुए लेखानुदान पारित किया जा सके। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के संबंध में भी लेखानुदान पारित किया जाना आवश्यक होगा।

सरकार की नीतियों से देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे जनता को अपनी क्षमता का अहसास हुआ है। देश की शक्ति उसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और उसकी जन-एकता में निहित है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान आपने जिस समर्पण की भावना, बुद्धिमता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है, वह राष्ट्र को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।

मैं इस सत्र में आपका अपने कार्यों में जुटने का आह्वान करता हूँ, और आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द

[Text of the President's Address in English]

Honourable Members,

I welcome you to this Session of Parliament.

The 10th Lok Sabha has accomplished substantially its tasks and the country has been guided through momentous changes in every sphere. I take this opportunity to congratulate all of you for your dedicated service to the nation.

The Nation celebrated the 125th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi which was marked by a large number of significant activities in different parts of the country and abroad. An important landmark was the institution of the Gandhi Peace Prize for Social, Political and Economic Transformation through Non-violence and other Gandhian methods. The first Gandhi Peace Prize was conferred upon Dr. Julius K. Nycrcrc. The Anniversary concluded with a solemn function on 31st January, 1996 at the Bapu Kutir in the Valmiki Mandir Complex in New Delhi where Gandhiji used to stay.

The law and order situation in the country has been under control. Government would continue to exercise extreme vigilance in the coming months to ensure that relations between different communities and groups continue to be harmonious.

Terrorism and insurgency have been curbed. Separatist tendencies have been contained to a very large extent. In this context the performance of the security forces has been creditable. However, the incident of arms drop in Purulia in West Bengal has highlighted the need for constant vigilance. In this connection, investigations into the incident, and its national and international ramifications, are being pursued vigorously. Steps are being taken to ensure effective policing of the air corridors of the country.

In Jammu and Kashmir, due to the

concerted drive by security forces against militants and foreign mercenaries, coupled with the acceleration of development activities, there is a perceptible change in the overall situation. The revival of political activities has been made possible. Parliament passed a balanced budget in 1995-96 and for the first time in many years the Plan outlay is expected to be spent fully on development schemes without any diversion for meeting the Non-Plan resources gap. Though Government had to seek further extension of President's Rule upto 17th July, 1996, it remains committed to the restoration of representative Government in the State at the earliest.

In the North-East several initiatives have been taken to tackle the economic backwardness of the region. The North-East Council has emerged as an effective institution for implementing developmental activities. The Sixth Schedule to the Constitution was amended for giving more powers to the Autonomous District Councils of Karbi Anglong and North Cachar Hills in Assam.

The economic scenario has been continuously improving. The Gross Domestic Product has shown a substantially faster rate of growth in the years subsequent to 1991-92. In 1994-95, this had increased to 6.3%. Gross Domestic Savings at Current prices improved in 1994-95 and was 24.4% of GDP. Industrial production increased by 12% in the first 6 months of the current year over the corresponding period last year, showing a strong revival.

Along with this, exports have gone up further by 24.17% in the first 8 months of the current financial year. Imports have also grown as a consequence of the overall growth of the economy, and the industrial sector in particular. Foreign exchange reserves are at a comfortable level of about \$ 16 billion.

The annual rate of inflation which had

almost reached 17% in August, 1991 has been controlled and in the current year, the inflation rate has been brought down to around 5%, which is the lowest in the last 7 years. As a result of the strong support to the agricultural sector, foodgrain production and stocks have reached very comfortable levels. The availability of various items of mass consumption has been maintained. The Public Distribution System has been strengthened and by introducing the Revamped Public Distribution System, additional concessions have been given for those living in the poorest areas of the country.

The small scale industries sector accounts for about 40% of the output in manufacturing and 34% of the country's total exports. It has recorded a growth of 10% during 1994-95 and accounted for employment of 146 lakh persons by the end of 1994-95. Export of goods by this sector are estimated to have increased from Rs. 13,883 crore in 1991-92 to Rs. 26,400 crore in 1994-95.

In the khadi and village industries sector, sales have reached a level of over Rs. 4069 crore in 1994-95. This sector accounted for employment to 53.46 lakh persons in 1994-95. A Rs. 1000 crore consortium credit has been given to KVIC this year for the first time. Out of this, KVIC had sanctioned projects costing about Rs. 235 crore by the end of January 1996 to generate additional employment for about one lakh persons.

Our agricultural strategy has been to increase production through the best use of soil and water in an integrated fashion. During the Eighth Plan, Rs. 1100 crore have been allocated for the restructured National Watershed Development Project for Rainfed Areas. The coverage of Drought Prone Areas Programme has also been increased to 946 blocks of 149 districts in 13 States. Coverage of the Desert Development Programme has been further extended to 227 blocks of 36 districts in 7 States. These programmes are being implemented with the active

participation of the watershed community.

Foodgrain production in 1994-95 achieved a new record of 192 million tonnes. The production of sugar also reached a record level of nearly 145.85 lakh tonnes in 1994-95. Government has built up a buffer stock of 5 lakh tonnes of sugar this year, as a precaution against possible fluctuations in availability and prices.

Disbursement of agricultural credit through institutional agencies is expected to reach a level of Rs. 26,450 crore in 1995-96 as against Rs. 21,113 crore in 1994-95. The consumption of chemical fertilizers during 1994-95 was 135.64 lakh tonnes. It is expected to further increase to 156.64 lakh tonnes in 1995-96.

Government has been acutely sensitive to the needs of the poor. The programmes of direct alleviation of poverty have been expanded, as reflected in substantial increases in allocations for rural development, employment generation, housing, rural water supply, etc.

Under the Indira Awas Yojana, about 20 lakh houses were constructed between 1985-96 and 1994-95. However, in 1995-96 this programme has been further stepped up by the undertaking a massive programme of construction of 10 lakh houses with a budget provision of Rs. 1000 crore and is progressing in full swing. Besides, steps have been taken to 'augment housing facilities for other sections as also government servants.

The Prime Minister's Rozgar Yojana which aims at providing self-employment opportunities to educated unemployed youth, had benefited 1,96,154 persons during 1994-95. For 1995-96, loans under the scheme are planned to reach 2.6 lakh persons.

As the Honourable Members know, the Government has launched the National Social Assistance Programme to provide for Old Age Pensions, Maternity Benefit and lumpsum payment on the

death of the primary bread earner in poor families. Complementing this package is a pioneering scheme of Group Life Insurance which includes subsidized premiums for the poor.

An Integrated Urban Poverty Eradication Programme was launched in November 1995 to tackle the problem of urban poor in an integrated manner in all 345 class-II towns with a population ranging between 50,000 to 1 lakh. A provision of Rs. 100 crore has been made in the current financial year for the Programme.

Government has strengthened the role and powers of the Panchayats and Nagarpalikas in all Centrally Sponsored Schemes operating at the, district level and below. This initiative has also ensured the emergence of more than 10 million women as leaders and decisionmakers at the grassroot level. Similarly, the State are being asked to empower these bodies with adequate financial and administrative responsibilities.

Substantial enhancement has been made in the allocations for Schemes of Special Central Assistance for Special Component Plan, Post-Matric Scholarships, National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and Aid to Voluntary Organizations. The Government has also revised the rates of maintenance and other allowances under the Post-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste and Scheduled Tribes students.

A National Commission for Safai Karamcharis has been set up to monitor the implementation of the National Scheme for Liberation and Rehabilitation of Safai Karamcharis still engaged in night soil removal. Since the inception of the Scheme, about 94,000 such persons have been trained for other vocations and 2.5 lakhs have been rehabilitated.

The National Backward Classes Finance and Development Corporation has so far disbursed Rs. 131.64 crore for

self-employment ventures. To enable the OBC candidates to compete on equal terms with general candidates in various recruitment tests and examinations, the Government has provided financial assistance to 122 coaching centres so far.

The National Minorities Development and Finance Corporation has established linkages with State channelising agencies. Loans are being disbursed for self-employment. The Wakf Act, 1995, for effective and democratic administration of Wakf Boards has been brought into force with effect from 1st January, 1996. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 has been enacted to provide equal opportunities for persons with disabilities. It has also been decided to set up a National Finance and Development Corporation for the Disabled with an authorised share capital of Rs. 400 crore. A Bill to set up a National Trust to provide total care to persons with Mental Retardation and Cerebral Palsy has been introduced in the Lok Sabha.

The ongoing immunisation of children against six vaccine-preventable disease has already yielded encouraging results. In keeping with the global goal of eradication of polio by 2000 AD, a supplemental dose of oral polio vaccine was administered to more than 7.5 crore children in the age group 0-3 years throughout the country on 9th December, 1995 and the exercise was repeated on 20th January, 1996. The Pulse Polio Immunisation will be continued in future years also.

The allocation for the education sector has been steadily increased as part of the Government's commitment to achieve the target of allocation of 6% of GDP by the year 2000 AD. To realise the goal of Universal Elementary Education, 110 Districts would be brought within the ambit of the District Primary Education Programme by the end of the Eighth Plan. A National Elementary Education Mission has been launched to cover all

children up to the age of 14 years by the turn of the century. As part of the National Literacy Mission, Total Literacy Campaigns have been further extended to 368 districts and the Post Literacy Campaigns to 159 districts in the country. A major National Programme of Nutritional Support to children in Primary Schools covering about 11 crore children from classes I to V over a three year period was launched on 15 August, 1995.

There has been a remarkable improvement in the industrial relations scenario in the country over the last 5 years. There is a significant decrease in the number of strikes and lock outs and number of mandays lost. Government is committed to successfully implement the Employees' Pension Scheme introduced in November, 1995, which provides for the first time life long social security to about 19 million industrial workers and their families.

To bring our arbitration law in tune with the international thinking on the subject, an Ordinance called "The Arbitration and Conciliation Ordinance, 1996" has been promulgated. With this and the other steps taken to establish Alternative Dispute Resolution Mechanisms, it is hoped that India will soon emerge as a pioneer in this field in the South-Asian Region.

The achievements of our scientists in the past year have been noteworthy and give us confidence for the future.

Successful launches of INSAT-2C and IRS-1C satellites last December once again demonstrated our capability to design, build and operate state-of-the-art space systems, which will be vital for the development of our telecommunication, television, meteorological and resources survey programmes. We plan to launch INSAT-2D during 1996-97, and INSAT-2E and IRS-1D during 1997-98. We have also made good progress in

developing the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle GSLV, for launching our INSAT class of satellites.

During the year, the country's tenth nuclear power reactor at Kakrapar commenced operation and was stabilised satisfactorily. The research reactors at Trombay have supplied more than 60,000 kits for diagnosis and treatment to more than 300 medical institutions all over the country.

During 1995-96, the situation in some parts of India's immediate neighbourhood remained uncertain in security terms. Pakistan's continuing attempts to acquire sophisticated weaponry and uranium enrichment technology have been a matter of serious concern for us. Pakistan's attempts heighten tensions in our region and are likely to trigger an arms race. We have every confidence in the capability of our armed forces to defend the nation. Government is determined to ensure their capability in this regard. I am sure honourable members would, in this context, join me in commending the armed forces for their professionalism and dedication.

As a result of the concentrated efforts of our scientists engaged in defence research, the Light Combat Aircraft was unveiled in November 1995 and test flights would commence by the end of this year. The development of the Main Battle Tank Arjun has been completed with a view to its induction. The DRDO has developed a high performance supercomputer using multi-processor technology, which has met a long-felt need and which enhances our self-reliance in this field.

In the foreign affairs sphere, our relations with our neighbours were further strengthened. Our traditionally close ties with Bhutan were reinforced during The year. The visit to India of the former Prime Minister of Nepal, Mr. Manmohan Adhikari, in April 1995

and of the present Prime Minister Mr. Shree Bahadur Deuba earlier this month, contributed to developing closer mutual understanding. The inauguration by the Prime Minister of the Indira Gandhi Memorial Hospital in the Maldives in April 1995 is testimony to our commitment to amity and cooperation with that country. Our relations with Sri Lanka were marked by cordiality and trust. Our trade with Bangladesh increased as did contacts between the peoples of the two countries. The momentum in our relations with China was maintained with a continuing dialogue at the highest levels. Our efforts resulted in promoting good relations with all our neighbours in South Asia, with the sole exception of Pakistan. We urge the Government of Pakistan to eschew its path of confrontation with India and respond constructively to our repeated offer of a bilateral dialogue to resolve all outstanding issues in accordance with the Shimla Agreement.

A landmark in SAARC's progress was achieved last year with the operationalisation of the South Asia Preferential Trading Arrangement (SAPTA) from December 7, 1995. The signing of a trilateral Memorandum of Understandings on transit by India, Iran and Turkmenistan, which seeks to establish a viable surface route between India and Central Asia for commercial and other links, was an important event in the development of our links with Central Asia. ASEAN has agreed to full dialogue partnership status for India. This reflects the growing, mutually beneficial relationship between India and ASEAN.

Our relations with the Russian Federation continued to be close. Further areas for cooperation in economic, cultural and other fields were identified. The India-United States relationship registered steady growth, in particular in the economic and commercial areas. Political and economic cooperation with countries in the African continent was promoted through high-level visits to and

from Mali, Mauritius, Namibia, Zimbabwe, Egypt, Burkina Faso and Ghana.

India took the lead in articulating the political, economic, social and other concerns of the developing countries in international forums like the World Summit for Social Development in Denmark in March, 1995; the UN General Assembly's 50th anniversary Special Commemorative Meeting in October, 1995; and the 11th Non-aligned Summit in Colombia in the same month. Consistent with its commitment to the objective of complete nuclear disarmament within a specified time-frame, India is participating actively in the negotiations for a Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. At the same time, we view the indefinite extension of the Nuclear Non-Proliferation Treaty as an obstacle to universal nuclear disarmament as it seeks to legitimise the nuclear arsenals of nuclear-weapon states.

As this Session will be a brief one, only essential legislation will be taken up during this Session. Some Ordinances promulgated since the last Session will be placed before Parliament. A Statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1996-97 will be laid before you for the purpose of passing Vote on Account authorising expenditure for a part of that year. Vote on Account in respect of the States under the President's Rule would also need to be passed.

The policies of the Government have put the country on the path of growth enabling the people to realise their potential. The strength of the country lies in the strength of its economy and the unity of its people. During the last four and a half years, your dedication, wisdom and vision have left an imprint that will guide the nation into a brighter tomorrow.

I commend you to your tasks in this Session and wish you success.

JAI HIND